तो इस प्रकार से कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये लेकिन भारत सरकार और प्रधान मंत्री कहती हैं कि बजट एलाऊ नहीं करता है। अभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये भत्ता बढ़ाया गया है तो उसको बजट ने कैसे एलाऊ किया ? यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। आखिर यह विरोधाभास क्यों है ? जितने पेन्शन पाने वाले हैं उनकी पेंशन की रकम को बढ़ाया जा रहा है फिर केन्द्रीय सरकार का बजट अनुसूचित और आदिम जातियों के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिये एलाऊ क्यों नहीं करता है ? इसलिये इस सरकार की मंशा क्या है, अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में यह सरकार कोई भी कानून बनायेगी तो उस पर अमल भी करेगी, इस बात का विश्वास नहीं होता। छुआछूत सम्बन्धी जो विधेयक है वह पिछले सत्र में ही पास होने वाला था लेकिन उसको जानबूझ कर लटकाया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि वह न आ सके। मुझे तो ऐसा अनुमान हो रहा है कि इस सेशन में भी विधि मंत्री उसको नहीं लायेंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे। अब इस समय गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा।

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTY-EIGHT REPORT

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): I beg to move:

"That this House do agree with the Sixty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th November, 1970."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Sixty-Eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 18th November, 1970."

The motion was adopted.

15.31 hrs.

RESOLUTION RE: LAW AND ORDER SITUATION IN WEST BENGAL-*Contd.*

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव के लिए साढ़े पांच घण्टे का समय नियत किया गया था जिसमें से तीन घंटे 12 मिनट का समय हो चुका है ओर अब दो घंटे 18 मिनट शेष रहते हैं। आज पहला भाषण श्री जगन्नाथ राव जोशी का होगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री नाथ पाई जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसी विषय पर कुछ दिन पहले चर्चा हुई है। वास्तव में यह कोई नयी समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में 1967 के चुनाव के उपरान्त सन् 1969 में फिर चुनाव हुआ। उसके बाद वहां पर एक नयी सरकार बनी परन्तु वह भी टिक नहीं सकी। आज फिर राष्ट्रपति महोदय का शासन वहां पर जारी है। वहां पर राष्ट्रपति शासन चालू होने के उपरान्त, वहां की जो स्थिति थी उसमें कुछ परिवर्तन आयेगा, ऐसी जो कल्पना थी उस कल्पना पर भी पानी फिर गया है। पिछले तीन चार दिनों के अखबारों में ही जिस प्रकार की खबरें वहां से आ रही हैं उनको अगर पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि वहां की स्थिति कितनी गम्भीर रूप धारण करती चली जा रही है। वहां पर लेजिस्लेटिव विभाग के जो सेक्रेटरी थे उनकी भी हत्या कर दी गई है। इस प्रकार